Punjab under IRDP and JRY during 1992-93 and 1993-94 is as under:-

(Rs. in lakhs)

Programme	Central allocation
	1992-93
IRDP	203.00
JRY	1361.74
	1993-94
	264.00
	1291.27

(b) and (c) No such Report has been brought to the notice of this Ministry.

(d) Both the schemes viz. IRDP and JRY are closely monitored regularly through periodical Progress reports on both physical and financial aspects, as well as through field inspection by Block/district/State level staff, periodical Meetings of central and state officials, workshop of Project Directors etc. from time to time in order to ensure that funds provided under the programmes are effectively utilised. The Centre has also introduced the scheme of Area Officers wherein senior officers undertake field inspection in the respective states allocated to them.

Setting up of regional CAPART Committee in the country

2435. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Centre has decided to set up Regional CAPART (Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology) Committee in different parts of the country;

(b) if so, what would be the main objectives of setting up such CAPART; and

(c) the steps taken to set up the CAPART in different States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) to (c) The Executive Committee of Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) in its meeting held on 17.6.1994 has approved a proposal to decentralise CAPART by setting up Regional Committees. All States would be covered by the Regional Committees. Further details are being worked out.

पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन

2436. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में अत्यन्त पिछड़े हुए 120 जिलों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार ने अपने प्रयासों के आधार पर एक नए अतिरिक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि समय-समय पर गठित की गई समितियों ने ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा शुरु किए गए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के कारण अपेक्षित लाभ न मिलने के बारे में सरकार को बताया है ; और

(च) यदि हां, तो इस नये कार्यक्रम के क्रियान्वयन में क्या एहतियात बरती गई है ताकि देश को वांछित लाभ मिल सके ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान देश के 120 पिछड़े जिलों की पहचान की है जहां बेरोजगारी और अल्परोजगार की बहुतायत है अतः यहां ग्रामीण रोजगार के प्रयासों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। जवाहर रोजगार योजना की निधियों के 20 प्रतिशत और न्यूनतम 700 करोड़ रुपये इन जिलों में गहन जवाहर रोजगार के लिए रखे गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत निधियां जिला ग्रामीण एजेन्सी/जिला परिषद को प्रदान की जाती हैं, जो जिले के अन्तर्गत बेरोजगारी और अल्प-रोजगार क्षेत्रों का पता लगाते हैं वे इन क्षेत्रों में जिले की निर्धारित विभिन्न योजनाओं में से कार्यों को शुरू करवाते हैं। इसी प्रकार की योजनाओं की श्रेणी में सभी मौसमों की सड़कों को बनवाना, लघु सिंचाई कार्य, भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, जल सकलीकरण ढांचे, बंजर भूमि विकास फार्म वानिकी आदि आते हैं ताकि ग्रामीण रोजगार को और स्थायी बनाया जा सके और क्षेत्र के सूखे को दूर किया जा सके। वे प्राथमिक स्तरों विशेष रूप से पिछड़े हुए जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक मण्डियों जैसे ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ बनाने की योजनाएं अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों से उचित पूरक निधियों की मदद से शामिल कर सकते हैं। जिसे उपरोक्त बताई गई योजनाओं में से उचित योजनाएं शामिल करके एक व्यापक कार्य योजना तैयार करेंगे जिसे जिलों में जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इन जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ङ) जी नहीं।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पहचान किये गये 120 पिछड़े जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. महबूबनगर
3. वारांगल
4. खम्माम
5. पूर्व गोदावली
6. नालगौंडा
7. प्रकाशम
8. अनंतपुर
9. कुरनूल

बिहार

10. पलामु
11. पश्चिम सिंहभूम
12. गुमला
13. रांची
14. डुमका
15. गया
16. हजारीबाग
17. पालिगंज
18. गन्डवा
19. सिन्दीह
20. सहारसा
21. मुंगेर
22. वैशाली
23. मुजफ्फरपुर
24. दरभंगा
25. सुपल
26. छपरा
27. जामुई
28. गोडा
29. भागेपुरा
30. भागलपुर
31. अभुआ
32. नवादा

गुजरात

33. पंचमहल
34. बलसाड
35. सूरत
36. बडोदरा
37. अमरेली
38. सुरेन्द्रनगर

जम्मू व काश्मीर

39. डोडा
40. उधमपुर

कर्नाटक

41. गुलबर्गा
42. कोलार
43. धारवाड़
44. बीजापुर
45. टुमकुर
46. चित्रदुर्गा
47. बेलरी
48. बीदर

मध्य प्रदेश

49. बस्तर
50. बिलासपुर
51. झबुआ
52. पश्चिम निमाड
53. सरगुजा
54. रायपुर
55. मांडला
56. रायगढ
57. धार
58. शहडौल
59. सिओनी
60. सिद्धी
61. पूर्वी निमाड
62. जबलपुर
63. बेतुल
64. राजनंदगांव
65. दुर्ग

महाराष्ट्र

66. धूले
67. नासिक
68. थाने
69. यावतमूल
70. अमरावती
71. नांदेड
72. बांदरा
73. चन्द्रपुर
74. बुदलाना
75. अकोला
76. पुणे
77. अहमदनगर
78. सांगली
79. शोलापुर
80. बीड़
81. औरंगाबाद

उड़ीसा

82. कोरापुट
83. मयूरभंज
84. कटक
85. सम्बलपुर
86. सुरेन्द्रगढ़
87. कालाहांडी
88. कियोंझर
89. गंजम
90. फूलबनी

राजस्थान

91. उदयपुर
92. बनासबाड़ी
93. डूंगरपुर
94. सवाई माधोपुर
95. बाड़मेर
96. अजमेर

तमिलनाडु

97. साउथ अरकोट
98. छांगेलपट्टु
99. तांजेवर

100. धर्मापुरी
101. छिदमबारनेर
102. रामानाथपुरम

उत्तरप्रदेश

103. इलाहाबाद
104. सीतापुर
105. गाजीपुर
106. हरदोई
107. सोनभदर
108. बलिया
109. मिर्जापुर
110. पिथौरागढ़
111. पौढीगढ़वाल
112. अलमोड़ा
113. बांदा
114. बहराईच

पश्चिमी बंगाल

115. मेदनीपुर
116. बुच बिहार
117. वर्धमान
118. बांकुड़ा
119. पुरुलिया
120. बीरभूम

"Training of trainers" or Panchayat Raj Programme

2437. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have a programme called "Training of Trainers" for Panchayat Raj Programme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether this programme has been implemented in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details therof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) With the enactment of the Constituion (73rd Amendment) Act, 1992 and subsequent amendments made in the State legislations on Panchayati Raj it is expected that a large number of new candidates would be elected to Panchayats. In order to familiarise these person with the Panchayati Raj System, great emphasis is being given to a massive training programme at the national and state levels. As a part of these Training efforts, the Training of Trainers has been organised at three selected national institutions. But the major part of these training efforts will have to be organised by the State Governments through their own institutions like SIRDs, ETCs, ATIs etc.

(c) and (d) The Ministry of Rural Development has addressed all States including Andhra Pradesh regarding training programmes for Panchayati Raj functionaries. In the Training of Trainers programme conducted by the National Institute of Rural Development, Hyderabad, participants from Andhra Pradesh have also been trained. Now the Government of Andhra Pradesh would take necessary steps to organize training at the state level and below.

Drinking water mission in Andhra Pradesh

2438. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) to what extent the drinking water problem in district of Nalgonda, Medak, Nizamabad in Andhra Pradesh has been covered by the "Drinking Water Mission"; and

(b) how many villages and habitations would still be left in above